

फायर टेक्नीशियन कोर्स के फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था का निदेशक गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने फायर टेक्नीशियन, फायरमैन और लाइब्रेरियन कोर्स की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने वाली निजी संस्था भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट, चेन्नई के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को एसओजी की टीम चेन्नई से गिरफ्तार कर जयपुर लाई है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, विशेषकर फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती में फर्जी डिग्रियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान संदिग्ध पाया गया। प्रारंभिक स्तर पर पटवारी भर्ती से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की गई, लेकिन वहां गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद जांच का फोकस फायरमैन भर्ती पर किया गया, जहां बीएसएस



निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन

संस्थान से बैकडेट में डिग्रियां जारी होने के ठोस सबूत सामने आए। एसओजी ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पृष्ठताछ के आधार पर हिंडीन (करीली) स्थित एएस फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट के संचालक श्यामवीर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में सामने आया कि यह संस्थान बीएसएस से एंफिलिएटेड है। इसके बाद एसओजी ने बीएसएस के चेन्नई और दिल्ली स्थित कार्यालयों की तलाशी ली, जहां बड़ी संख्या में बैकडेट में जारी की गई डिग्रियां और प्रमाण-पत्रों से

- फायरमैन और लाइब्रेरियन कोर्स की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने वाली निजी संस्था भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट, चेन्नई के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को गिरफ्तार किया**

जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। सबूत जुटाने के बाद कोर्ट से वारंट प्राप्त कर बीएसएस के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया।

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान को यूजीसी या किसी भी वैधानिक संस्था से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद यह संस्थान वॉकिशनल कोर्स के नाम पर फायरमैन, फायर टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन सहित कई कोर्सेज की डिग्रियां जारी कर रहा था।

जांच में सामने आया कि बीएसएस ने फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हुए देशभर में अपने नेटवर्क का विस्तार किया। संस्था से करीब 1० हजार इंस्टीट्यूट जुड़े, जिनमें से लगभग 7 हजार अभी सक्रिय हैं। इन

संस्थानों और दलालों के माध्यम से हजार से अधिक कोर्सेज की डिग्रियां ऑन-डिमांड जारी की जाती थीं।पड़ताल में यह भी सामने आया कि हर इंस्टीट्यूट का एक दलाल होता था, जो अभ्यर्थियों को झंसे में लेकर उनकी जानकारी बीएसएस कार्यालय भेजता था। इसके बाद मांगी गई तारीख के अनुसार बैक डेट में डिग्री और प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाते थे।एसओजी अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पृष्ठताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

एसओजी ने आमजन और नियोजक संस्थाओं से अपील की है कि किसी भी डिग्री या प्रमाण-पत्र के आधाार पर चयन से पहले उसका पूर्ण और विधिवत सत्यापन अवश्य करें।

ड्रोन व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में 1० जनवरी 2०26 को प्रस्तावित वीवीआईपी के आगमन कार्यक्रम को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था को प्राविात होने की आशंका को देखते हुए पुलिस अकादमी क्षेत्र के आसपास ड्रोन और पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

महिंद्रा की एक्सयूवी7एक्सओ और एक्सईवी9एस का अनावरण

जयपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में होटल जयपुर मैरियट में अपनी दो नई दमदार एक्सयूवी7एक्सओ और एक्सईवी9एस का भव्य लॉन्च किया। यह कार्रकम बेहद शानदार रहा, जिसमें मौजूदा और नए ग्राहकों की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया।

- इच्छुक ग्राहक इसे 14 जनवरी से बुक कर सकते हैं**

लॉन्च समारोह का उद्घाटन के एस मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल के एस गहलोत, करण गहलोत व आराधना गहलोत, ऑटोवर्ल्ड के असुपम सांखला तथा निखित शाह, आरएसएम महिंद्रा एंड महिंद्रा व अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में दोनों वाहनों का अनावरण किया गया, जिसके बाद ग्राहकों ने इनकी विशेषताओं को करीब से देखा और आनंद लिया। एक्सयूवी7एक्सओ के इस नए मॉडल की शुरुआती क्रीमव पेडोल व्हेरीएंट के लिए 13.66 लाख रुपए और डीजल व्हेरीएंट के लिए 14.96 लाख



लॉन्च समारोह का उद्घाटन के एस मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल के एस गहलोत, आराधना गहलोत ने किया ।

रुपए रखी गई है। ये क्रीमते पहले 40,000 ग्राहकों के लिए इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम हैं। नई एक्सयूवी7एक्सओ को पहले से ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन, अपडेटेड केबिन और कई नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इच्छुक ग्राहक इसे 14 जनवरी से बुक कर सकते हैं।

नई एक्सयूवी7एक्सओ को ग्राहक छह व्हेरीएंट्स में से चुन सकते हैं, जिसमें , 3, 5, 7, 7 और 7 शामिल हैं, जो चार इंजन ऑप्शन में आते हैं। इसके अलावा, इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

महिंद्रा की ई-एसयूवी लाइनअप में 9, 6 और 4०0 के साथ शामिल हो गया है। क्रीमव 19.95 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

महिंद्रा एक्सईवी9एस का डिज़ाइन इसे बाकी एसयूवीज़ से अलग बनाता है। इसमें एक ब्लैक-आउट ग्रिल, एल आकार के एलईडी डीआरएलएस, व्हिंकल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और प्रंट पेंसिल्यार पर एक पिक्सल स्टायल एलईडी लाइट बार मिलता है।

जयपुर। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना "मनरेगा" को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी सरकार द्वारा योजना का नाम बदलकर वीबी-जी-राम-जी करने और इसमें किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान में कांग्रेस ने 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक के विरोध प्रदर्शनों का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है।

कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार नाम बदलकर और नियमों में बदलाव कर इस ऐतिहासिक योजना को कमजोर करना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस ने इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने की रणनीति बनाई है।

जहां एक तरफ कांग्रेस मनरेगा बचाओं के नारे के साथ सड़कों पर उतर रही है। वहीं बीजेपी ने भी वीबी-जी-राम-जी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है।

आने वाले दिनों में राजस्थान की

आरपीएससी सचिव बताए नोटिस तामील के बाद भी पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 से जुड़े मामले में आरपीएससी सचिव को 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान वीसी से जुड़ने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इस दौरान सचिव सभी जरूरी दस्तावेज भी साथ रखें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में नोटिस जारी करने के बाद उनकी तामील में हो चुकी है, लेकिन आयोग की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और केस के अंजोइसी भी हाज़िर नहीं हुए। ऐसे में आयोग सचिव इस संबंध में अपना उचित स्पष्टीकरण दें।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर

पांच आरोपित गिरफ्तार

जयपुर। चित्रकूट थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों को दुबई से संचालित नंबरों के माध्यम से सट्टेबाजी के लिए आईडी (लाइन) उपलब्ध करवाई जा रही थी। पुलिस अब इस मामले में दुबई कनेक्शन की भी गहन जांच कर रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए

अजमेर निवासी साहिल खान के साथ नागौर निवासी इब्राहिम खान, दीलत अली, इमरान खान और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके साथ एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 5० से अधिक बैंक खाते मिले हैं। जिनमें सट्टेबाजी की रकम द्वांसफर की जा रही थी। पुलिस ने इन खातों में करीब दो लाख रुपये की रकम होल्ड भी करवा दी है।

मनरेगा का नाम बदलने पर छिड़ा सियासी संग्राम

- राजस्थान में 10 जनवरी से कांग्रेस का हल्लाबोल**

राजनीति में यह मुद्दा शहर से लेकर गांव की चौपालों तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में लंबे समय से फर्जीबाड़ा और भ्रष्टाचार फल-फूल रहा था। फर्जी जांब कार्ड सरपंचों के पास मिलते थे और मजदूरों के हक का पैसा बिचौलिया खरा रहे थे।

नए कानून के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाए हुए पारदर्शिता लाई गई है। सरकार ने रोजगार के दिन 1०0 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं। राठौड़ ने कहा कि आजीविका मिशन के शब्दों को जोड़ने से यदि राम नाम बन गया, तो इस पर आपत्ति करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि 2००4 से अन्न तक खर्च हुए कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये में से 8.53 लाख करोड़ रुपये अकेले बीजेपी सरकार ने खर्च किए हैं।

बकाया नगरीय विकास कर की वसूली के लिये टीम अलर्ट मोड पर

जयपुर। नगर निगम जयपुर के आयुक्त डॉ. गौरव सेनी के निर्देशनुसार मानसरोवर जोन में नगरीय विकास कर की बकाया राशि की वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। इस क्रम में बुधवार को सिविल लाइंस जोन क्षेत्र में स्थित कुल 6 संपत्तियों पर बकाया नगरीय विकास कर की राशि की वसूली की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी, प्रशासनिक एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

कार्रवाई के दौरान संपत्तियों पर बकाया राशि जमा कराने हेतु कुर्कफ की प्रक्रिया अपनाई गई। जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम द्वारा बकायदारों पर कुर्कफ की कार्रवाई की गई जिसमें दो संपत्तियों पर कुर्कफ की गई तथा शेष चार प्रकरणों में वारंट/कुर्कफ से पूर्व ही समझाइश के दौरान 11 लाख 71 हजार 998 रुपये बकाया नगरीय विकास कर जमा कराया गया।

इसके अतिरिक्त झोटवाडा, वैशाली नगर जोन में भी राजस्व शाखा द्वारा 6 सम्पत्तियों पर नगरीय विकास

- आरपीएससी सचिव को 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान वीसी से जुड़ने के आदेश दिए**

अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 18० पदों भर्ती निकाली थी। जिसमें मुख्य परीक्षा में करीब तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं आयोग ने इनमें से सिर्फ 4 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया और आयोग के परिणाम के अनुसार अन्य अभ्यर्थी न्यूनतम अनिवार्य चालीस फीसदी अंक भी नहीं ला सके। याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जिन्होंने

पांच आरोपित गिरफ्तार

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनरेगा को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। जूली ने कहा कि सीएम का मनरेगा के बदले हुए प्रावधानों का समर्थन करना राजस्थान के ग्रामीण परिवेश और गरीब वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। यह विडंबना है कि जिस पंचायती राज व्यवस्था से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले भजनलाल शर्मा से गांवों को उम्मीद थी, वे आज ग्राम सभाओं के अधिकारों का गला घोटने वाली योजना के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं।

जूली ने कहा कि, जिस व्यवस्था ने उन्हें पहचान दी, आज उसे ही कमजोर करने में वे केंद्र का खक्ति हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री स्वयं ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद दिल्ली के आलाकमान की भाषा बोल रहे हैं। वे राजस्थान के हितों की रक्षा

उपमुख्यमंत्री ने कलश यात्रा का किया शुभारंभ

जयपुर।विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के निंदड़ में आयोजित होने जा रही जगद्गुरु परम आदरणीय स्वामी रामभद्राचर्य जी की दिव्य श्रीराम कथा एवं 1००८ कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ से पूर्व बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा में उपमुख्यमंत्री प्रिया कुमार जी ने सहभागिता निभाते हुए विधिवत पूजा-अर्चना के बाद कलश यात्रा की रवाना किया। कलश यात्रा कुकरखेड़ा मंडी से प्रारंभ होकर निंदड़ स्थित यज्ञ स्थल तक पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भक्ति और श्रद्धा के साथ यात्रा में भाग लिया। मार्ग में जगह-जगह भव्य स्वागत द्वार बनाए गए, वहीं जय श्रीराम के गगनभेदी जयघोष से पूरा क्षेत्र धर्ममय वातावरण से सराबोर हो गया। उपमुख्यमंत्री प्रिया कुमारी ने कहा कि भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से परिपूर्ण इस कलश यात्रा में मातृशक्ति की अभूतपूर्व सहभागिता ने आयोजन को और भी दिव्य बना दिया है।उन्होंने इस भव्य एवं अनुकरणीय आयोजन के लिए समस्त आयोजक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मातृशक्ति की अभूतपूर्व सहभागिता ने आयोजन को और भी दिव्य बना दिया है।उन्होंने इस भव्य एवं अनुकरणीय आयोजन के लिए समस्त आयोजक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

- चार प्रकरणों में वारंट/कुर्कफ से पूर्व ही समझाइश के दौरान 11 लाख 71 हजार 998 रुपये बकाया नगरीय विकास कर जमा करवाया**

कर राशि 79 लाख 84 हजार 39० रुपये की बकाया वसूली की गई। नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सेनी ने कहा कि नगर निगम के बकाया नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी समय पर नगरीय विकास कर जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कुर्कफ एवं सौज की कार्रवाई जारी रहेगी। शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व वसूली अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम जयपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आगामी दिनों में भी बकाया नगरीय विकास कर करदाताओं के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

1.25 लाख की अवैध शराब जब्त

जयपुर। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के जरिए उदयपुर से आनंद (गुजरात) भेजी जा रही करीब 1 लाख 25 हजार रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। तस्कर शराब को कलर पेंट की बाल्टियों पर पशु आहार का लेबल लगाकर सील पैक कर ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से भेज रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर कानन शर्मा ने बताया कि पुलिस को जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी में संदिग्ध सामग्री की सूचना मिली थी। इस पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर प्रथम नीरज पाठक के सुपरविजन और सहायक पुलिस आयुक्त अमेर सुरेंद्र सिंह राणावत के निदेशन में त्वरित कार्रवाई की गई। इसके बाद थानाधिकारी राजेश गौतम के नेतृत्व में उप निरीक्षक जगदीश नारायण के साथ हैड कांस्टेबल संजय जाखड़, उमेश चंद , प्रदीप , सुरेश और कांस्टेबल रलीराम की टीम गठित की गई।

याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी यह परिणाम ममाना, अव्यावहारिक और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में आशंका जताई गई है कि परीक्षा के मूल्यांकन में वृटिपूर्ण मॉडल उत्तर और अत्यधिक कठोर अंकन कर मपीनी अंदाज में कोपियां जांची गई हैं। ऐसे में परीक्षा परिणाम को रद्द कर नए सिरे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर संशोधित परिणाम जारी किया जाए।

मनरेगा पर आलाकमान की भाषा बोल रहे सीएम : टीकाराम जूली

- जूली ने कहा कि, जिस व्यवस्था ने उन्हें पहचान दी, आज उसे ही कमजोर करने में वे केंद्र का सक्रिय हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री स्वयं ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद दिल्ली के आलाकमान की भाषा बोल रहे हैं**

करने के बजाय केवल दिल्ली के संदेशवाहक बनकर रह गए हैं। जूली ने कहा कि, अब तक मनरेगा का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब इसे 6०:4० के अनुपात में बांटकर राज्यों पर 40 प्रतिशत फंड का बोझ डालना तानाशाही है। इससे राजस्थान के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होगा। यह सोधे तौर पर संघीय ढांचे को नष्ट करने की साजिश है।

जूली ने कहा- वीबी जी राम जी केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि मनरेगा के मूल सिद्धांतों पर हमला है। मनरेगा

एक कानूनी अधिकार था, जबकि नई योजना इसे केंद्र की मजी पर निर्भर बनाना चाहती है। मनरेगा ने गांवों में रोजगार देकर पलायन रोका और महिलाओं को आर्थिक संबल दिया। भाजपा को गांधी और मनरेगा, दोनों खटकते हैं, इसलिए इस हक को छीनने की साजिश रची गई है।जूली ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री दिल्ली की कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश के गरीब मजदूरों के हक की बलि चढ़ा देंगे? उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी इस निचविरोधी नीति का सदन से लेकर सड़क तक कड़ा विरोध करेगी।

सार-समाचार विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आज से

जयपुर । विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 8 व 9 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक संजीव कुमार नाजरी राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने बताया कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा होंगे। गुह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, मुख्य सचिव राजस्थान वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गुह विभाग भास्कर ए.सावंत, उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा व जयपुर मुख्यालय पर युदधस्थापित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा सभी रेंज आईजी, सभी जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 12 जनवरी 195० को नई दिल्ली में किया गया। इसी क्रम में 60 वाँ राष्ट्रीय डीजी/आईजी पुलिस सम्मेलन नवम्बर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। जिसकी सिफारिशों के अनुक्रम में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में ०2 दिन में दस सत्र आयोजित होंगे। जिनमें विकसित भारत में पुलिसिंग सम्बन्धी विषयों पर महत्वपूर्ण व्याख्यान होंगे।

जयपुर केंद्रीय कारागार में फिर मिला मोबाइल फोन

जयपुर। घाटगेट स्थित केंद्रीय कारागार में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल प्रशासन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान जेल परिसर से मोबाइल फोन बरामद होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची लाल कोठी थाना पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर उसके ईएमआई नंबर और सिम नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने वार्ड नंबर-7 की बैक नंबर-3 में स्थित टॉयलेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टॉयलेट में छुपाकर रखा गया एक की-पैड मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ। इसके बाद जेल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना लालकोठी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेल कारापाल अशोक कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात बंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन के ईएमआई नंबर और सिम कार्ड के माध्यम से यह पता लगाने में जुटी है कि मोबाइल किस बंदी का है और जेल के भीतर यह कैसे पहुंचा।

जल जीवन मिशन घोटाले में जांच का दायरा सीमित क्यों

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही जांच को सिर्फ दो फर्मों तक सीमित रखने के मामले में ईडी और राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। एफ़िंटंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक ऑफ़ेंस करणन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। इसके बावजूद भी केवल दो टेका फर्म के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर जांच की गई है। याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी, लेकिन केवल दो फर्मों के अलावा अन्य की ओर से किए गए

- याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी**

फर्जीवाड़े की न तो जांच की गई और ना ही अब तक एफआईआर दर्ज की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मामलों में प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। ईडी की ओर से एएसजी भरत व्यास ने कहा कि ईडी ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।

जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब देने के लिए मामले को सुनवाई तीन सप्ताह बाद करना तय किया है।